



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 19, 2007/ज्येष्ठ 29, 1929

No. 280]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 19, 2007/JYAISTHA 29, 1929

जनजातीय कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2007

सा.का.नि. 437(अ).—निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिन्हें केंद्रीय सरकार अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) की धारा 14 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त नियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्दिष्ट है, प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं; पैंतालीस दिन की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऐसे किसी आक्षेप या सुझाव पर, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त हों, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई है, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत  
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2007

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

- (1) "अधिनियम" से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) अभिप्रेत है;
- (2) "वास्तविक जीविका आवश्यकताओं" से वन भूमि या वन आधारित उपयोगों से उत्पाद के उपभोग और/या बिक्री के माध्यम से स्वयं तथा परिवार की, और घर या घरेलू प्रयोजनों के लिए पत्थरों और ईंधन लकड़ी की निरंतर आवश्यकताओं की पूर्ति अभिप्रेत है;
- (3) "दावेदार" से ऐसा व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, परिवार या समुदाय अभिप्रेत है, जो अधिनियम में सूचीबद्ध अधिकारों में से किसी अधिकार की मान्यता और उसे निहित करने के लिए आवेदन करता है।
- (4) "वन अधिकार समिति" से नियम 26 (2) के अधीन ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित कोई समिति अभिप्रेत है;
- (5) "अन्य परम्परागत अधिकार" से ऐसा कोई अन्य परम्परागत अधिकार अभिप्रेत है, जिसका रुढ़िगत रूप से वन निवासी अनुसूचित जनजाति या अन्य परम्परागत वन निवासियों द्वारा उपभोग किया जाता है, चाहे वह अभिलिखित है या नहीं, और इसमें परम्परागत कृषि प्रथाओं का अधिकार शामिल होगा;
- (6) अधिनियम की धारा 2 (ग) और धारा 2 (ण) में "वनों में अथवा वन भूमि पर प्राथमिक रूप से निवास करने और निर्भर रहने वाले" से दावेदार अभिप्रेत है जो वास्तविक जीविका की आवश्यकताओं के लिए ऐसे वन या वन भूमि पर निर्भर करते हैं, परंतु उनका अनन्यतः और अनिवार्य रूप से ऐसे वन या वनभूमि पर निवास करना आवश्यक नहीं है।
- (7) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (8) "सतत उपयोग" का वही अर्थ होगा, जो जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 2 के खण्ड (ण) में है, अर्थात् जैव विविधता के घटकों का उपयोग ऐसी रीति से और ऐसी दर पर करना जिसका परिणाम जैव विविधता में दीर्घावधि गिरावट नहीं होती है, जिसके द्वारा वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने की संभावना को बनाए रखा जा सके।

## अध्याय 2

### ग्राम सभा और विभिन्न समितियां

3. ग्राम सभा और इसके कृत्य: (1) ग्राम सभा को निम्नलिखित के लिए प्राधिकार होगा :—

- (क) वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा का अवधारण करना;
- (ख) उप-खंड स्तर समिति से संपर्क करना;

- (ग) अधिनियम के अधीन ऐसे दावे प्राप्त करना, उन्हें सुनना और विवादों को निपटाना;
- (घ) वन अधिकारों के दावेदारों की सूची तैयार करना और दावों का एक रजिस्टर रखना; और
- (ङ) वन अधिकार संबंधी दावों पर एक संकल्प पारित करना तथा उसे अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उप-खंड उपबंधों समिति को भेजना।

(2) ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति ऐसी ग्राम सभा के वयस्क सदस्यों के दो तिहाई से कम नहीं होगी, जिसमें कम से कम तैंतीस प्रतिशत महिलाएं होंगी। जहां किसी गांव में अनुसूचित जनजातियों और गैर-अनुसूचित जनजातियों की विषम जनसंख्या है, वहां गणपूर्ति गठित करने के लिए कम से कम दो तिहाई अनुसूचित जनजाति के सदस्य होंगे और प्राचीन जनजातीय समूहों तथा पूर्व कृषक समुदायों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व होगा।

#### स्पष्टीकरण :-

इस नियम के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित गांव की ग्राम सभा का गठन करेंगे :

- (क) पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 या राज्य में प्रवृत्त अन्य किसी तत्स्थानी विधि के अधीन, अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति जिनके नाम गांव में पंचायत के लिए निर्वाचक नामावली में शामिल हैं, जिसमें छोटा गांव या छोटे गांवों का समूह है, जो अपने कार्यकाल का प्रबंधन अपनी परम्परा और रीति-रिवाजों के अनुसार करते हैं तथा ग्राम सभा का गठन इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु करते हैं तथा इसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत और उप-खंड स्तरीय समिति को देते हैं।
- (ख) उन राज्यों में जहां पंचायतें हैं और जो अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, पंचायत की ग्राम सभा, यदि अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बड़े गांव में छोटी ग्राम इकाइयों में ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करने के लिए प्राधिकृत हैं और यह इसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत तथा उप-खंड स्तरीय समिति को देते हैं।
- (ग) अधिनियम की धारा 2 (त) (iii) के मामले में, ऐसे गांव के वयस्क सदस्य एक ग्राम सभा का गठन करने का संकल्प पारित कर सकते हैं और इसकी सूचना समीप की ग्राम पंचायत (तों) और उप-खंड स्तरीय समिति को दे सकते हैं;
- (घ) उन राज्यों में जहाँ पंचायतें नहीं हैं, पारम्परिक ग्राम संस्थाओं के चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, वयस्क सदस्य ग्राम सभा का गठन करने के लिए संकल्प कर सकते हैं और इसकी जानकारी उप-खंड स्तरीय समिति को दे सकते हैं।

4. राज्य सरकार इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, उप-खंड स्तरीय समिति, जिला स्तरीय निगरानी समिति का गठन अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजन हेतु करेगी।

**5. उप-खंड स्तरीय समिति :-** उप-खंड स्तरीय समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों से किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) सभापति के रूप में उप-खंड अधिकारी;

(ख) एक उप-खंड का भारसाधक वन अधिकारी

(ग) जिला पंचायत द्वारा नामनिर्देशित ब्लॉक/तहसील पंचायतों के तीन सदस्य, जिनमें से दो अनुसूचित जनजाति के होंगे, अधिमानतः जो वन निवासी हैं या प्राचीन जनजातीय समूहों के हैं और जहां अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य नहीं है, वहां दो सदस्य जो अधिमानतः अन्य परम्परागत वन निवासी हैं तथा इनमें कम से कम एक महिला सदस्य होगी; अथवा संविधान की छठी अनुसूची में सम्मिलित क्षेत्रों में, स्वशासी जिला परिषद/क्षेत्रीय परिषद अथवा अन्य समुचित आंचलिक स्तर पर नामनिर्देशित तीन व्यक्ति, जिनमें कम से कम एक महिला सदस्य होगी;

(घ) सदस्य सचिव के रूप में जनजातीय, कल्याण विभाग का उस उप-खंड का भारसाधक अधिकारी अथवा जहां ऐसा अधिकारी उपलब्ध नहीं है, वहां जनजातीय कार्यों का तत्समान भारसाधक अधिकारी;

**6. उप-खंड स्तरीय समिति के कृत्य :-** उप-खंड स्तरीय समिति :-

(क) ग्राम सभा या वन अधिकार समिति को वन और राजस्व मानचित्र तथा निर्वाचक नामावलियां उपलब्ध;

(ख) संबंधित ग्राम सभाओं के सभी संकल्पों को मिलाएगी;

(ग) ग्राम सभाओं द्वारा प्रदान किए गए मानचित्रों और ब्यौरों को समेकित करेगी;

(घ) दावों की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभाओं के संकल्पों और मानचित्रों की जांच करेगी;

(ङ) किन्हीं वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा के संबंध में ग्राम सभा के बीच विवादों को सुनेगी तथा उन्हें अधिनिर्णीत करेगी;

(च) ग्राम सभा के संकल्पों से व्यथित व्यक्तियों की याचिकाओं को सुनेगी;

(छ) अंतर उप-खंड दावों के लिए अन्य उप-खंड स्तरीय समितियों के साथ समन्वय करेगी;

(ज) सरकारी अभिलेखों का समन्वय करने के पश्चात वन अधिकारों के ब्लॉक वार/तहसीलवार प्रारूप अभिलेख तैयार करेगी;

(झ) अंतिम विनिश्चय के लिए वन अधिकारों के प्रारूप अभिलेख के साथ दावे उप-खंड अधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय समिति को भेजेगी;

(ण) अधिनियम और नियम 25 (4) के उद्देश्यों, उपबंधों और प्रक्रियाओं के बारे में कार्यशालाओं और अन्य माध्यमों से जागरूकता उत्पन्न करेगी;

(त) दावेदारों को दावों के प्रपत्र की सहज और निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, जैसा इन नियमों के उपाबंध - 1 में दिया गया है।

7. **ज़िला स्तरीय समिति :** जिला स्तरीय समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों से किया जाएगा, अर्थात्:

- (क) सभापति के रूप में, जिला कलेक्टर या उपायुक्त;
- (ख) संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी या उप वन संरक्षक;
- (ग) जिला पंचायत द्वारा नामनिर्देशित जिला पंचायत के तीन सदस्य, जिनमें से दो अनुसूचित जनजाति के सदस्य होंगे, अधिमानतः वन निवासी या प्राचीन जनजाति समूहों के सदस्य हों, तथा जहां कोई अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं, वहां दो सदस्य जो अधिमानतः अन्य परम्परागत वन निवासी होंगे और इनमें कम से कम एक महिला सदस्य होगी; या संविधान की छठी अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्षेत्रों में तीन सदस्य स्वशासी जिला परिषद/क्षेत्रीय परिषद के हों, इनमें कम से कम एक महिला सदस्य हो।
- (घ) सदस्य सचिव के रूप में जिले के जनजातीय कल्याण विभाग के भारधारक अधिकारी या जहां ऐसा अधिकारी उपलब्ध नहीं है वहां जनजातीय कार्य का तत्समान भारसाधक अधिकारी।

8. **ज़िला स्तरीय समिति के कृत्य :** (1) जिला स्तरीय समिति निम्नलिखित कार्य करेगी :-

- (क) यह जांच करना कि सभी दावों का अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समाधान किया गया है;
- (ख) उप-खंड स्तरीय समिति द्वारा तैयार किए गए वन अधिकारों के दावों और अभिलेखों पर अंतिम रूप से विचार करना तथा उन्हें अनुमोदित करना;
- (ग) उप-खंड स्तरीय समिति के आदेशों से व्यथित व्यक्तियों की याचिका सुनना;
- (घ) अंतर-जिला दावों के विषय में अन्य जिलों के साथ समन्वय करना;
- (ङ) सुसंगत सरकारी अभिलेखों, जिसमें अधिकारों का अभिलेख भी है, में वन अधिकारों को समाविष्ट करने के लिए निदेश जारी करना;

(2) जिला स्तरीय समिति निम्नलिखित कार्य भी करेगी :

- (क) वन अधिकारों के अवधारण में सरकारी दस्तावेजों और अन्य सुसंगत सूचना तक पहुंच प्राप्त करने में ग्राम सभा को सुकर बनाना तथा यदि आवश्यक हो, तो तकनीकी सहायता प्रदान करना;
- (ख) अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के संबंध में प्रसार की प्रक्रिया तथा जागरूकता कार्यक्रम सुनिश्चित करना;
- (ग) यह सुनिश्चित करना कि ग्राम सभाएं एक मुक्त, खुले और प्रतिनिधित्वकारी रूप से महिलाओं की पूर्ण और अनिवार्य भागीदारी के साथ काम कर रही हैं;

(3) जिला कलेक्टर या उपायुक्त निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा :

- (क) जिला स्तरीय समिति द्वारा अंतिम रूप दिए जाने के बाद वन अधिकारों के अभिलेख प्रकाशित कराना;
- (ख) यह सुनिश्चित करना कि अधिनियम के अधीन वन अधिकारों और हक के अभिलेख की एक प्रमाणित प्रति, जैसा इन नियमों के उपाबंध - 2 में विनिर्दिष्ट है, संबंधित दावेदार को दी जाती है तथा गांव में सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक रूप से चिपकायी जाती है।

9. राज्य स्तरीय निगरानी समिति : राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों से किया जाएगा, अर्थात:

- (क) सभापति के रूप में, मुख्य सचिव;
- (ख) सचिव, राजस्व विभाग;
- (ग) सचिव, जनजातीय कार्य विभाग;
- (घ) सचिव, वन विभाग;
- (ङ) प्रधान मुख्य वन संरक्षक;
- (च) आयुक्त, जनजातीय कार्य या समकक्ष, सदस्य सचिव के रूप में;
- (छ) जनजातीय सलाहकार परिषद, के तीन अनुसूचित जनजाति के सदस्य, जो जनजातीय सलाहकार परिषद के सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित वन एवं वन्य जीवन, जनजातीय और लिंग के मुद्दों पर तीन स्वतंत्र विशेषज्ञ और जहां कोई जनजातीय सलाहकार परिषद नहीं है वहां राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित वन एवं वन्य जीवन, जनजातीय तथा लिंग के मुद्दे पर तीन स्वतंत्र विशेषज्ञ।

10. राज्य स्तरीय निगरानी समिति के कृत्य : राज्य स्तरीय निगरानी समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे:

- (क) राज्य में वन अधिकारों को मान्यता देने, उनके संस्थापन तथा उन्हें निहित करने की प्रक्रिया की मानीटरिंग करना;
- (ख) वन अधिकारों की मान्यता और निहित करने की प्रक्रिया की प्रभावशीलता की मानीटरिंग के लिए मानदण्ड और सूचक विकसित करना;
- (ग) अन्य राज्य सरकारों और अंतर-राज्यीय दावों के मामले में राज्य स्तरीय निगरानी समितियों के साथ समन्वय करना;
- (घ) वन अधिकारों की मान्यता, संस्थापन और निहित करने की प्रक्रिया पर एक छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करना और ऐसी विवरणियों और रिपोर्टों को नोडल अभिकरण को प्रस्तुत करना, जिन्हें नोडल अभिकरण द्वारा मांगा जाए;
- (ङ) अधिनियम की धारा 8 में यथा उल्लिखित ऐसी किसी सूचना मिलने पर, राज्य स्तरीय निगरानी समिति अधिनियम के अधीन उक्त प्राधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई कर सकती है जहां यह अपराध सिद्ध हो जाता है और सुधारात्मक उपाय करना है।
- (च) अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित पुनः स्थापन की मानीटरिंग ।

**अध्याय 3****वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के वन अधिकार**

11. **अधिभोग का अधिकार :** (1) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन अधिकारों का दावा किए जाने की दशा में, परिवार में नाभिकीय परिवार और उनके अवयस्क बालक और परिवार पर पूरी तरह या आंशिक रूप से आश्रित व्यक्ति सम्मिलित हैं।
- (2) अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (6) के अधीन समुदाय के अधिभोग के अधीन भूमि के मामले में अथवा अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन सामान्य अधिभोग में वास्तविक उपयोग के अधीन क्षेत्र को मान्यता दी जाए और समुदाय को अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि प्रदान की जाए।
12. **निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार :-** सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार, जिसे अलग-अलग राज्यों में जिस नाम से जाना जाता हो, पर वास्तविक जीविका की आवश्यकताओं के लिए विचार किया जाएगा।
13. **लघु वन उत्पाद पर अधिकार :-** (1) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अधीन अधिकारों में सभी लघु वन उपज, इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि वे राष्ट्रीयकृत हैं या पूर्वतः प्रतिबंधित या निषिद्ध हैं और राज्य अधिनियमों और नियमों, आदेशों और तदधीन जारी निदेशों में उपबंधित सभी मदें शामिल होंगी।
- (2) ग्राम सभा लघु वन उत्पाद, की प्रकृति को सुनिश्चित करेगी जिसे परम्परागत रूप से अधिनियम के अनुसार गांव की सीमाओं के अंदर या बाहर संग्रहीत किया गया है, और उप-खंड स्तरीय समिति को सूचना देगी।
- (3) वन अधिकारों के धारकों द्वारा सभी ऐसे लघु वन उत्पाद तक पहुंच, उनका संग्रहण, उपयोग और निपटान रॉयल्टी मुक्त होगा।
- (4) इन अधिकारों का प्रयोग उन क्षेत्रों तक बढ़ाया जाएगा, जहां ऐसे लघु वन उत्पाद-परम्परागत रूप से संग्रहीत किए जाते हैं और इसमें गैर-संलग्न और अविशिष्ट, वन भूमि और सामुदायिक वन संसाधन सम्मिलित हैं।
- (5) लघु वन उत्पाद के अधिकार के उपयोग में जमा करने वाले या उनके सहकारियों या उनके समूहों द्वारा स्थानीय स्तर का प्रसंस्करण, मूल्य वर्धन और इनके विपणन सम्मिलित हैं।
- (6) अधिकारों के उपयोग में सिर पर बोझा या साइकिल और हाथगाड़ी के माध्यम से लघु वन उत्पाद को निकटस्थ गांव या संग्रह बिंदु तक परिवहन शामिल हैं।
- (7) ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अधीन अधिकारों में उक्त गौण वन उत्पाद को जमा करने में किसी विनाशकारी प्रथा के निरंतर उपयोग और रोकथाम का दायित्व भी सम्मिलित हो।

14. **अन्य सामुदायिक अधिकारों और पात्रताओं का अधिकार :** (1) इस समुदाय का, जो परम्परागत रूप से जिन जलाशयों का उपयोग करता है, उक्त जलाशयों की मछली और अन्य उत्पादों पर, इनका निरंतर उपयोग सुनिश्चित करते हुए अधिकार होगा।

- (2) बिना किसी करार के और उक्त समुदाय की पूर्व सूचित स्वीकृति के बिना उक्त जलाशयों पर किसी सरकारी अभिकरण द्वारा कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।
- (3) यायावर और चारागाही समुदायों के उनके सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार के प्रयोग में परम्परागत, रुढ़िगत और मौसमी उपयोक्ता, वन भूमि सम्मिलित है, जो अनिवार्यतः एकल संसक्त क्षेत्र नहीं बनाती और इसे अन्य अनुसूचित जनजातियों या परम्परागत वन निवासियों के साथ बांटा जा सकता है।
- (4) चारागाही और यायावरों की जनजातियों तथा अन्य मौसमी उपयोक्ताओं से अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अधीन उनके अधिकारों के अवधारण के लिए दावों का अवधारण या तो व्यक्ति सदस्यों, समुदाय या परम्परागत सामुदायिक संस्थान के माध्यम से किया जाए और इसका सत्यापन उस समय किया जाए जब ये व्यक्ति, समुदाय या उनके प्रतिनिधि या उनके परम्परागत संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित हों।

15. **आवास और आवासन के सामुदायिक कार्यकाल का अधिकार :** (1) प्राचीन जनजातीय समूहों और पूर्व कृषि समुदायों के लिए आवास का वही अर्थ होगा, जिसमें सामुदायिक वन संसाधन और विशेष रूप से गैर-संलग्न और अविशिष्ट सम्मिलित हैं।

- (2) प्राचीन जनजातियों या कृषि-पूर्व समुदाय के सदस्यों की ओर से उनके आवास के अधिकार के अवधारण का दावा अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ड) के अधीन समुदाय या परम्परागत समुदाय के माध्यम से किया जाए और इनका सत्यापन उस समय किया जाए जब उक्त समुदाय या उनके प्रतिनिधि या उनके परम्परागत संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित हों।
- (3) जहां कहीं संभव हो, ग्राम सभा और उप-खंड स्तरीय समिति के साथ प्राचीन जनजातीय समूह और पूर्व कृषि समुदाय परम्परागत संस्थानों के परामर्श से उनके रुढ़िगत आवास का अवधारण और विलगन कर सकते हैं।
- (4) यदि प्राचीन जनजातीय समूहों और पूर्व कृषि समुदायों की दशा में वे अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ड) के अधीन अपने अधिकार का दावा नहीं करते हैं, तो उप-खंड स्तरीय समिति स्वयं इसे कर सकती है और संबद्ध ग्राम सभा को पूर्व सूचना देकर उक्त सुभेद्य समुदायों के वन अधिकारों का अवधारण करने की प्रक्रिया आरंभ कर सकती है।

16. **विवादित भूमियों पर अधिकार :** (1) यदि विवादित भूमियों पर अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (च) के अधीन दावा किया जा रहा है तो इसमें "माने गए" आरक्षित वन, में जहां वन बंदोबस्त की प्रक्रिया गलत अभिलेखों, या विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन नहीं करने, सहित किसी शीति में पूरी नहीं की गई है वहां वन भूमि में या, जहां भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 या किसी अन्य सुसंगत विधि की तत्स्थानी धारा के अधीन अंतिम अधिसूचना अभी जारी की जानी है वहां वन भूमि में या ऐसी भूमि, सम्मिलित होगी जिस पर विवादित दावे विभिन्न सरकारी विभागों के बीच चल रहे हैं और इस प्रकार लोगों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।



- (2) उक्त विवादित भूमि पर अधिकारों की परिकल्पना दावेदार के पक्ष में होगी, जब तक कि मामले में सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद अन्यथा निर्णय न लिया जाए।

17. **पट्टे, लीज़ और अनुदानों के संपरिवर्तन का अधिकार :** (1) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (छ) के अधीन दावा की जा रही वन भूमियों के हक में पट्टों, लीज़ और अनुदानों के संपरिवर्तन के अधिकार में, अन्य के साथ, वह भूमि जो विभिन्न सरकारी विभागों के बीच विवादित बन गई है, या वे वन भूमियां, जिनका अंतरण कार्य पूरा नहीं हुआ है; या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के नारंगी क्षेत्रों में पट्टे, एक साली लीज़, महाराष्ट्र में डालही की भूमियां या कृषि वानिकी के लिए लीज़, एग्रो-सिल्वी या फायर लाइन भूखंड या भूमियां, जिनकी लीज़ का नवीकरण नहीं हुआ है अथवा जिन्हें विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना ही खाली करा लिया गया है; वन ग्रामों में पट्टे और जारी किए गए पट्टे, जिन्हें सम्यक कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना रद्द या समाप्त कर दिया गया, सम्मिलित हैं।

18. **वन ग्रामों और अलेखबद्ध व्यवस्थापनों को राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तित करने का अधिकार :** जब अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ज) के अधीन वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में संपरिवर्तित करने के अधिकारों का दावा किया जा रहा हो तब:

- (क) ऐसी वन भूमि पर जो राजस्व ग्राम नहीं है या इसका एक भाग नहीं है कोई व्यवस्थापन पात्र माना जाएगा; और
- (ख) वन ग्रामों या उक्त व्यवस्थापनों से बाहर से सृजित की राजस्व गांवों के निवासियों की ऐसी भूमि, वास्तविक आजीविका की आवश्यकताओं के लिए निरंतर उपयोग की जाएगी और इसे किसी भी रूप में पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाने वाले वाणिज्यिक उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

**टिप्पणी :-** उपरोक्त नियम 11 से 18 के अधीन प्रदत्त सामुदायिक अधिकार, अन्य संक्रमणीय, अंतरण योग्य नहीं होंगे, और लीज़ या किराए पर नहीं दिए जाएंगे।

19. **सामुदायिक वन संसाधनों की सुरक्षा, पुनरुत्पादन, संरक्षण या प्रबंधन का अधिकार :-** (1) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (झ) के अधीन अधिकारों के निर्धारण से पूर्व ग्राम सभा सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार के स्वरूप और विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया आरंभ करेगी, और नियम 31 के उप-नियम (3) में उल्लिखित साक्ष्य को विचार में लिया जाएगा।

(2) जहां दो या दो से अधिक समुदायों का एक ही सामुदायिक वन संसाधन पर अधिकार है, वहां संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा समुदायों के एक संयुक्त समूह का आयोजन किया जाएगा और वह संबंधित ग्राम सभा के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में अपने अधिकारों का उपयोग करेगा।

(3) सामुदायिक वन संसाधन की रुढ़िगत सीमाओं की पुष्टि के लिए संबंधित ग्राम सभा की वन अधिकार समितियों द्वारा आपसी सहमति की तिथि पर सभी संबंधित ग्राम सभाओं की सहमति के साथ सामुदायिक वन संसाधन की निर्धारण प्रक्रिया आरंभ की जाएगी और लिखित रूप में संबंधित ग्राम सभा और उप-खंड स्तरीय समिति को सूचित किया जाएगा।

(4) रुढ़िगत सीमाओं को मौजूदा कानूनी सीमाओं के परिवर्तन के रूप में नहीं लिया जाएगा।

**20. स्वशासी जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों में अधिकार :** ऐसे वन अधिकारों का, जिन्हें किसी राज्य विधि या किसी स्वशासी जिला परिषदों या क्षेत्रीय परिषदों में या किसी राज्य की विधियों संबंधित जनजातियों के परम्परागत या रूढ़िगत विधियों के अधीन उपलब्ध अधिकारों के अधीन पहले से मान्यता प्राप्त है, उपयोग स्वशासी जिला परिषदों, क्षेत्रीय परिषदों, राज्य सरकारों या संबंधित जनजातियों की ऐसे परम्परागत या रूढ़िगत विधियों के अनुसार किया जाएगा।

**21. बौद्धिक संपदा और जैव विविधता का अधिकार :** (1) जब समुदाय के बौद्धिक संपदा तथा जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित परम्परागत ज्ञान और जैव विविधता की अभिगम्यता के अधिकार को अधिनियम की उप धारा (1) के खंड (ज) के अधीन मान्यता दी गई है, तब इस में आनुवांशिक संसाधनों, बीजों, दवाओं, स्वास्थ्य प्रथाओं, औषधीय पौधों, कृषि, जीव – जन्तुओं और वनस्पति के ज्ञान, खनिज तथा अन्य स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों और प्रथाओं सहित जैव विविधता संसाधनों से जुड़े परम्परागत विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अभिगम्यता, नियंत्रण, विकास और सुरक्षा के नियमन का अधिकार सम्मिलित होगा।

2) ग्राम सभा जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अधीन जैव विविधता प्रबंधन समिति के साथ मिलकर इसके द्वारा संरक्षित, निरंतर उपयोग में लाए गए और प्रबंधित जैव विविधता संसाधनों और उक्त जैव विविधता तथा सांस्कृतिक विविधता और ग्राम सभा द्वारा अभिलेखन के लिए ज्ञान प्रदाताओं द्वारा स्वैच्छिक रूप से घोषित व्यक्ति, समूह या सामुदायिक ज्ञान का प्रलेखन समन्वित कर सकेगी।

3) उप-नियम (2) में संदर्भित प्रलेखन ग्राम सभा की संपत्ति होगा और वह यह निर्णय लेगी कि इसके किस भाग या विषयवस्तु को जनता के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध कराया जाना है तथा किन शर्तों और निबंधनों के अधीन पक्षों के सामने अन्य भागों या सामग्रियों को प्रस्तुत किया जाना है।

4) ग्राम सभा राज्य जैव विविधता बोर्डों के साथ और उक्त प्रलेखित ज्ञान के प्रबंधन में सुरक्षित पादप किस्मों और किसानों के अधिकारों के प्राधिकरण के साथ समन्वय कर सकेगी ताकि बौद्धिक संपदा अधिकारों पर उपयुक्त बल डाला जा सके और इसके उपयोग से सभी को समान रूप से लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

5) ग्राम सभा बाहरी लोगों द्वारा जैव विविधता संसाधनों पर अभिगम्यता के विनियमन के लिए और संग्रह प्रभारों के उद्ग्रहण तथा आपसी लाभ की व्यवस्थाओं का पता लगाने के लिए जैव विविधता प्रबंधन समिति के साथ समन्वय कर सकेगी।

**22. स्वस्थाने पुनर्वास का अधिकार :** (1) जब अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ड) के अधीन स्वस्थाने पुनर्वास के अधिकार का दावा किया जाए तो विधिक रूप से बेदखल कराने या विस्थापित करने अथवा पुनर्वास के लिए विधिक पात्रता प्राप्ति का भार राज्य अथवा राज्य के तत्वाधान में कार्यरत अभिकरण के पास होगा।

(2) दावे या तो मूल निवास के संबंध में अधिकारिता रखने वाली ग्राम सभा के सामने अथवा उस स्थान की ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत किए जाएं, जहां दावेदार का वर्तमान निवास है।

23. विस्थापितों के लिए भूमि का अधिकार : (1) जब भूमि के अधिकार का दावा अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (8) के अधीन किया जाता है तो भूमि के मुआवजे के बिना विस्थापन का तथ्य, जैसा कि दावेदार द्वारा स्थापित किया जाए, अधिकार के लिए प्राथमिक आधार होगा।

(2) उन प्रयोजनों के लिए, जिनके लिए इसे अधिग्रहीत किया गया था, 5 वर्षों के अंदर उक्त भूमि का उपयोग सिद्ध करने का भार, राज्य अथवा राज्य के तत्वाधान में कार्यरत अभिकरण पर होगा।

(3) दावे या तो मूल निवास के संबंध में अधिकारिता रखने वाली ग्राम सभा के सामने अथवा उस स्थान की ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत किए जाएं, जहां दावेदार का वर्तमान निवास है।

#### अध्याय 4

##### वन अधिकारों के धारकों के कर्तव्य

24. वन अधिकारों के धारकों, ग्राम सभाओं और ग्राम स्तरीय संस्थाओं के कर्तव्य: (1) ग्राम स्तरीय संस्थाएं या ग्राम सभा अधिनियम की धारा 5 के अधीन आने वाले कर्तव्यों का निष्पादन किसी वन अधिकार के धारकों की ओर से कर सकती है तथा इसे निम्नलिखित अधिकार होंगे

(क) सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंध के लिए योजना तैयार करना और उक्त योजनाएं, मानक, पद्धतियाँ, प्रक्रियाएं अपनी संगत योजनाओं जैसे वन कार्यकारी योजनाओं, संरक्षित वनों और राष्ट्रीय उद्यानों की प्रबंधन योजनाओं, जैव विविधता योजनाओं, जलागम प्रबंधन योजनाओं और पारिस्थितिकी - विकास योजनाओं जैसी योजनाओं के सामंजस्य में हो सकेंगी;

(ख) सामुदायिक वन संसाधनों और जैव विविधता, वन, कैचमेन्ट क्षेत्रों, जल संसाधनों और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों सहित संसाधनों की अभिगम्यता और निरंतर उपयोग की सुरक्षा और विनियमन के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं सहित मानक तैयार करना और उन्हें अपनाना;

(ग) सामुदायिक वन्य जीवन प्रबंधन के लिए मानक तैयार करना;

(घ) संवेदनशील समूहों और महिलाओं के वन अधिकारों के हितों की रक्षा करते हुए संसाधन की सुरक्षा, संरक्षण, पुनर्जनन या प्रबंधन की प्रक्रियाएं विकसित करना जिसके अंतर्गत बाहरी व्यक्तियों की अभिगम्यता को अनुमति देने या मना करने का निर्णय लेना और शुल्क प्रभारित करना भी है; और

(ङ) ऐसे मानकों की निगरानी और कार्यान्वयन की पद्धतियां विकसित करना।

(2) ग्राम सभा

(क) इसके मानकों के कार्यान्वयन हेतु वन विभाग की या अन्य स्थानीय प्राधिकारियों की सहायता का अनुरोध कर सकेगी और ऐसे प्राधिकारी अपेक्षित सहायता प्रदान करेंगे;

- (ख) जहां इस अधिकार के उपयोग में इसके द्वारा सृजित मानकों का उल्लंघन किया गया है, जहां अनिवार्य हो, वहां सुधारात्मक कार्रवाई कर सकेगी, या संबंधित प्राधिकारियों को विधि के अनुसार कार्यवाही करने का निदेश दे सकेगी;
- (ग) संयुक्त वन प्रबंधन समिति, पारिस्थितिकी — विकास समिति, जलागम समिति, जैव विविधता प्रबंधन समिति या अन्य ऐसी कोई समितियों अथवा संस्थाओं, जो वन संसाधनों के प्रबंधन से जुड़े हैं, के कार्यों का मार्गदर्शन कर सकेगी;
- (3) यदि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (झ) के अधीन अधिकारों के उपयोग के विषय में ग्राम सभा और उपयोक्ता समूह के बीच कोई विवाद है तो ग्राम सभा का निर्णय तब मान्य होगा, जबकि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संवेदनशील समूहों और महिलाओं के वन अधिकारों को कोई हानि नहीं हो।

#### अध्याय 5

वन अधिकारों को निहित करने के लिए प्राधिकारियों के दायित्व और उसकी प्रक्रिया

25. प्राधिकारियों और अन्य व्यक्तियों को सुग्राही बनाने की प्रक्रियाएं : (1) नोडल अभिकरण —

- (क) यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम और नियमों के उद्देश्यों, उपबंधों और प्रक्रियाओं के विषय में जागरूकता कार्यक्रमों और क्षेत्रीय भाषाओं में मुद्रित पोस्टरों जैसी सामग्री सहित विभिन्न माध्यमों से जागरूकता लाई जा रही है;
- (ख) यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम और नियमों का अनुवाद और प्रकाशन सभी क्षेत्रीय भाषाओं में किया गया है तथा सभी ग्राम सभाओं, वन अधिकार समितियों एवं सरकार के सभी विभागों जिनके अंतर्गत पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जनजातीय और सामाजिक कल्याण तथा वन विभाग भी है, में इसके वितरण की व्यवस्था की गई है;
- (ग) प्रत्येक राज्य में अधिकारियों, नागरिक प्रतिनिधियों तथा गैर सरकारी संगठनों का पूर्वाभिमुखीकरण किया जाएगा, जिन्हें तब जागरूकता कार्यक्रमों में संसाधन व्यक्तियों के रूप में सहायता देने के लिए बुलाया जा सकता है;
- (घ) राज्य सरकारों के माध्यम से अधिनियम और नियमों के उद्देश्यों, उपबंधों और प्रक्रियाओं के बारे में जिला स्तरीय समितियों को सुग्राही बनाया जाएगा।
- (2) जिला स्तरीय समितियां पारम्परिक और अन्य साधनों से अधिनियम और नियमों के उद्देश्यों, उपबंधों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता अभियान चलाएंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि अधिनियम और नियम क्षेत्रीय भाषाओं में मुद्रित कर ग्राम, ब्लॉक और उप-खंड स्तर पर प्रमुख स्थानों और कार्यालय में वितरित किए गए हैं एवं विशेष रूप से इस बात को सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे कि यह जानकारी दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित आबादियों तक पहुंचती है।

(3) जिला स्तरीय समिति कार्यशालाओं और अन्य साधनों के माध्यम से उप-खंड स्तरीय समितियों के सदस्यों, पंचायती राज अधिकारियों, ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, वन, जनजातीय और सामाजिक कल्याण विभागों के अधिकारियों के बीच अधिनियम और नियमों के उद्देश्यों, उपबंधों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाएंगी।

(4) उप-खंड स्तरीय समिति उपखंड में प्रत्येक तहसील या ब्लॉक के लिए एक या अधिक जागरूकता शिविर लगाकर शिक्षकों, महिला समूहों, राजनैतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और वकीलों सहित ग्राम सभाओं, जिनके अंतर्गत वन अधिकार समिति के सदस्यों, नागरिक प्रतिनिधियों को अधिनियम और नियमों के उद्देश्यों, उपबंधों और प्रक्रियाओं के बारे में संवेदनशील बनाएंगी।

**28. ग्राम सभा द्वारा दावों को दायर करने और निर्धारण की प्रक्रिया :** (1) उप-खंड स्तरीय समिति इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख के तीन मास के अंदर ग्राम सभा की पहली बैठक की तारीखें अधिसूचित करेगी।

(1) पहली बैठक में ग्राम सभा अपने सदस्यों में से एक समिति का निर्वाचन करेगी जिसमें कम से कम सात सदस्य होंगे, जिनमें से तीन सदस्य अनुसूचित जनजातियों के, तीन महिला सदस्य और एक अन्य पारम्परिक वन निवासी सदस्य होगा; और जहां कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है, वहां कम से कम तीन सदस्य अन्य परम्परागत वन निवासी और तीन महिला सदस्य होंगे और उक्त समिति को वन अधिकार समिति कहा जाएगा एवं इसकी जानकारी संबंधित उप-खंड स्तरीय समिति को दी जाएगी।

(2) ग्राम सभा वन अधिकार समिति में, उप नियम (2) में उल्लिखित सदस्यों के अतिरिक्त, 7 सदस्यों से अनधिक का चयन कर सकेगी, यदि वे अनुसूचित जनजातियों, अन्य परम्परागत वन निवासियों और महिलाओं के समान अनुपात को ध्यान में रखते हुए ऐसी इच्छा रखते हैं, जैसा उप नियम (2) में निर्दिष्ट किया गया है।

(3) ग्राम सभा को सरकार की ओर से अनिवार्य अवसंरचना और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

(4) वन अधिकार समिति ग्राम सभा को उसके निम्नलिखित कार्यों में सहायता देगी —

- (i) ग्राम सभा की बैठकों का संचालन;
- (ii) निर्दिष्ट प्ररूप में दावे तथा उक्त दावों के समर्थन में साक्ष्य प्राप्त करना, पावती देना और धारण करना ;
- (iii) सरकारी पदाधिकारियों जैसे विद्यालय के शिक्षकों, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं, वन कर्मियों और पटवारियों से आवश्यक सहायता की मांग करना;
- (iv) इन नियमों में उपबंधित किए गए अनुसार दावों का सत्यापन करना;
- (v) यथा अपेक्षानुसार किसी प्राधिकारी या अभिकरण या व्यक्तियों से साक्ष्य या समर्थन की मांग करना;
- (vi) मानचित्रों सहित दावों और साक्ष्य के अभिलेख तैयार करना;
- (vii) वन अधिकारों पर दावेदारों की सूची तैयार करना;
- (viii) ग्राम सभा के सामने निर्णय हेतु दावे के स्वरूप और विस्तार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करना।

27. दावों का सत्यापन : (1) ग्राम सभा अपनी पहली बैठक में निम्नलिखित कार्य करेगी —

(क) दावों को आमंत्रित करना और इन नियमों के परिशिष्ट — 1 में यथा उपबंधित विनिर्दिष्ट प्ररूप में उक्त दावों को स्वीकार करने के लिए वन अधिकार समिति को प्राधिकृत करना तथा इन दावों को तीन मास के अंदर किया जाएगा;

परंतु ग्राम सभा इसके कारणों को अभिलिखित करने के बाद उक्त समय सीमा को बढ़ा सकेगी।

(ख) इसके समुदाय वन संसाधनों के निर्धारण की तारीख निश्चित करना और इसकी जानकारी आस-पास की ग्राम समाओं, जहां संभावित दोहराव हैं और उप-खंड स्तरीय समितियों को देना।

(2) ऐसा कोई दावा जो विनिर्दिष्ट प्ररूप के अनुसार नहीं है, उसे दोष सुधार के लिए वापस भेज दिया जाएगा और उसके बाद स्वीकार किया जाएगा।

(3) इन नियमों के अधीन सभी दावों के साथ नियम 31 में वर्णित एक से अधिक साक्ष्य संलग्न किए जाएंगे।

(4) ग्राम सभा दावेदार के दावे का निर्धारण करने के पहले उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय प्रदान कर सकेगी।

(5) दावेदार सुसंगत साक्ष्य प्राप्त करने में दावेदार वन अधिकार समिति की सहायता ले सकेगा।

(6) प्राप्त प्रत्येक दावे की वन अधिकार समिति की ओर से लिखित में पावती दी जाएगी।

28. वन अधिकार समिति द्वारा दावों के सत्यापन की प्रक्रिया : (1) संबंधित दावेदार को सम्यक्तः सूचना देने के बाद, वन अधिकार समिति :

(क) स्थल का दौरा करेगी और दावे के स्वरूप, विस्तार और स्थल के साक्ष्य का व्यक्तिगत रूप से सत्यापन करेगी; और

(ख) ऐसा कोई और अन्य साक्ष्य या अभिलेख प्राप्त करेगी अथवा दावेदार और गवाहों द्वारा दिया गया कोई मौखिक साक्ष्य प्राप्त करेगी।

(2) वन अधिकार समिति किसी प्राधिकारी से साक्ष्य की मांग कर सकती है, जो आवश्यक हो।

(3) तब वन अधिकार समिति दावे पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगी और निर्णय के लिए इसे ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत करेगी।

(4) यदि किसी अन्य गांव की परम्परागत या रूढ़िगत सीमाओं के अंदर परस्पर विरोधी दावे हैं अथवा यदि वन क्षेत्र को एक से अधिक ग्राम समाओं द्वारा उपयोग में लाया जाता है तो संबंधित ग्राम समाओं की वन अधिकार समितियां संयुक्त रूप से बैठक करके उक्त दावों के लाभ के स्वरूप के

बारे में करार करेंगी और इस कथित करारनामे को लिखित रूप में संबंधित ग्राम सभाओं को प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) ग्राम सभा या वन अधिकार समिति के जानकारी, अभिलेखों या दस्तावेजों के लिए लिखित अनुरोध पर राज्य सरकार के विभिन्न विभाग (सभी स्तरों पर) उन्हें वन अधिकार समिति या ग्राम सभा को प्रदान करेंगे और आवश्यकता और अपेक्षा के अनुसार उसे इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से स्पष्ट करेंगे।

(6) वन अधिकार समिति द्वारा एक मानचित्र संबंधित राजस्व और वन प्राधिकारियों के साथ मिल कर बनाया और सत्यापित किया जाएगा ! इस में पहचान योग्य पहचान चिन्हों को दर्शाते हुए प्रत्येक संस्तुत दावे के क्षेत्र को अलग से दर्शाया जाएगा।

29. वन अधिकार का निर्धारण : (1) ग्राम सभा, नियम 26 के उप नियम (2) के अनुसार पहली बैठक के बाद, वन अधिकार समिति के निष्कर्षों और सिफारिशों पर विचार करने के लिए आवश्यकतानुसार बैठक करेगी तथा उपयुक्त पाए गए संकल्प पारित करेगी, किन्तु यह पूर्व सूचना सहित प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बार होनी चाहिए।

(2) ग्राम सभा आवश्यक कार्यवाई के लिए इस प्रस्ताव की एक प्रति उप-खंड स्तरीय समिति को अग्रेषित करेगी।

(3) यदि कोई ग्राम सभा, अधिनियम की धारा 6 के अधीन अपने कार्यों का निष्पादन करने में असफल रहती है तो किसी दावेदार के आवेदन पर उप-खंड स्तरीय समिति उक्त कार्यों के निष्पादन हेतु कथित ग्राम सभा को एक सूचना भेजेगी और यदि ग्राम सभा दो माह के अंदर कार्यवाही आरंभ नहीं करती है तो दावेदार अपने दावे के निर्धारण के लिए सीधे उप-खंड स्तरीय समिति के पास जा सकता है।

30. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष उपबंध : पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में, अन्यथा, दावेदार, प्रवृत्त अधिनियमों, नियमों और विनियमों के अधीन, अन्यथा प्रश्नाधीन क्षेत्र में भूमि धारण करने और रहने का पात्र होगा।

31. वन अधिकारों के निर्धारण के लिए साक्ष्य : (1) अधिनियम की धारा 3 के अधीन वन अधिकारों की मान्यता और उन्हें निहित करने के लिए दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों में निम्नलिखित शामिल हैं, किन्तु ये इन तक सीमित नहीं हैं, अर्थात्—

(क) सार्वजनिक दस्तावेज, सरकारी अभिलेख जैसे राजपत्र, जनगणना, सर्वेक्षण और बंदोबस्त रिपोर्ट मानचित्र, उपग्रहीय चित्र, कार्यकारी योजनाएं, प्रबंधन योजनाएं, लघु योजनाएं, वन जांच रिपोर्ट, अन्य वन अभिलेख, अधिकारों के अभिलेख जिन्हें पट्टा या लीज़, जो भी नाम दिया गया हो (शर्त युक्त या अन्यथा समाप्त या अन्यथा), समितियों और आयोगों की रिपोर्टें, सरकारी आदेश, अधिसूचनाएं, परिपत्र, संकल्प और पत्र।

(ख) मतदाता पहचानपत्र, राशनकार्ड, पासपोर्ट, ऋण, बीमा और ऋण तथा गृहकर रसीदें, मूल निवास प्रमाणपत्र जैसे सरकारी प्राधिकृत दस्तावेज;

(ग) ग्राम सभा के सामने वृद्धों के बयान, ग्राम सभा के सदस्यों और अन्य पात्र अधिकार धारकों के

बयान को विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों के बयानों को जो पढ़ या लिख नहीं सकते हैं, लेखबद्ध करना;

- (घ) वास्तविक कार्य जैसे समतल करने, बंद, चैक बांध बनाने और इसी प्रकार की संरचनाओं सहित स्थायी सुधार;
  - (ङ) न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों, प्रारंभिक आपराधिक रिपोर्टों सहित अर्ध-न्यायिक और न्यायिक अभिलेख, जिसे चालान या रसीद के नाम से जाना जाता है;
  - (च) ऐसी वन अधिकार समिति द्वारा दावों के स्थल के सत्यापन की स्थानीय जांच रिपोर्ट, जिसे ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित और अनुमोदित किया गया हो;
  - (छ) प्रतिष्ठित संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा पूर्व अनुसंधान या अभिलेखन जिनके अंतर्गत नृविज्ञानियों द्वारा तैयार रिपोर्टें, प्रकाशन तथा भारतीय नृविज्ञान सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी है;
  - (ज) मानचित्रों, अधिकारों, विशेषाधिकारों, रियायतों, समर्थन देने वाले अभिलेखों सहित कोई अभिलेख जो रजवाड़ों के समय या प्रान्तीय अथवा अन्य ऐसे किसी मध्यवर्तियों से प्राप्त हुए हैं;
  - (झ) न्यायालय सहित प्राधिकारियों को दिए गए पूर्व आवेदन, ज्ञापन, याचिकाएं;
  - (ञ) ग्राम सभा के पूर्व संकल्प;
  - (ट) रीतिरिवाजों और परम्पराओं का लिखित विवरण, जो किसी वन अधिकार के उपयोग का चित्रण करता हो और जिसके पास परम्परागत विधि का बल हो।
  - (ठ) परम्परागत संरचनाएं या चित्र जो उसकी पुरातनता स्थापित करते हों या लंबे समय से स्वामित्व दर्शाते हों, जैसे कि पुराने सुधार, कुएँ, शमशान/कब्रिस्तान, पवित्र स्थल;
  - (ड) ऐतिहासिक विवरण, सर्वेक्षण रेखाचित्र और मानचित्रों के आरेख, तस्वीरें और परम्परागत साम्रादायिक वनों और आखेट के मैदानों, परम्परागत पहचान चिन्हों के ऐतिहासिक विवरण;
  - (ढ) मौखिक या लिखित जैनियोलॉजी, जिसमें पूर्व भूमि अभिलेख में उल्लिखित व्यक्ति के पुरखों का इतिहास हो या जिसे पुराने समय में गांव के वैध निवासी के रूप में मान्यता दी गई हो;
- (2) ग्राम सभा, उप-खंड स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति वन अधिकारों के निर्धारण में उपरोक्त उल्लिखित साक्ष्य में से एक से अधिक पर अधिमानतः विचार करेंगी :
- परंतु यदि दावेदार और किसी राज्य अभिकरण के बीच विवाद की स्थिति में जब तक कि अन्यथा सिद्ध न कर दिया जाए, दावेदार के पक्ष में परिकल्पना की जाएगी।
- (3) सामुदायिक वन संसाधन के साक्ष्य में निम्नलिखित शामिल होंगे:



- (क) सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार, इसे चाहे जिस नाम से बुलाया जाए;
- (ख) परम्परागत चारागाह, जलावन लकड़ी को जमा करने के क्षेत्र, पत्तीदार खाद, जड़ें और कन्द, चारा, वन्य खादय और अन्य लघु वन उत्पाद, मछली पकड़ने के स्थान, सिचाई प्रणालियां, मानव या पशुधन के उपयोग के लिए पानी के स्रोत, औषधीय पौधों का संग्रह, जड़ी बूटी देने वाले वैद्यों के क्षेत्र;
- (ग) भू-संरक्षण और जल संरक्षण संरचनाओं के अवशेष, पवित्र वृक्ष, पवित्र गुफाएं, पवित्र तालाब या नदी क्षेत्र, कब्रिस्तान या शव दाह गृह;
- (घ) वर्तमान आरक्षित वन जैसे संरक्षित वन या गोचर या अन्य सामान्य ग्राम भूमि के पूर्व वर्गीकरण के सरकारी अभिलेख, संयुक्त वन प्रबंधन से संबंधित वन विभाग से समझौता ज्ञापन, लघु वन उत्पाद संग्रह अधिकार की नीलामी, पूर्व या वर्तमान रूप से जारी चराई का अनुमति पत्र;
- (ङ) बड़े क्षेत्र की बहु प्रयोजन सोसायटी या वन श्रमिक सहकारी को सौंपे गए क्षेत्र, जिन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, पेड़ उगाने वाले सहकारियों को सौंपे गए क्षेत्र;
- (च) परम्परागत कृषि की प्रारंभिक या वर्तमान प्रथा।
- (4) अन्य परम्परागत वन निवासियों के निर्धारण के साक्ष्य में निम्नलिखित सम्मिलित है परन्तु यह इन तक सीमित नहीं है—

- (क) वास्तविक कार्य/परम्परागत संरचनाएं या चित्र, जो विशिष्टता या दीर्घ अवधि अधिभोग स्वामित्व स्थापित करते हों जिसमें कुएँ, कब्रिस्तान, पवित्र स्थान, मकबरे सम्मिलित हैं;
- (ख) आरंभिक भूमि अभिलेखों में उल्लिखित विवरण के अनुसार व्यष्टिक के पुरखों की लिखित वंशावली या आरंभिक समय से ग्राम के वैध निवासी के रूप में उसे मान्यता दी जा सके;
- (ग) ग्राम सभा, उप-खंड स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति वन अधिकारों के विनिश्चय के लिए कम से कम 75 वर्षों से तीन पीढ़ियों का अवधारण करने में इस नियम में उल्लिखित एक से अधिक साक्ष्य पर विचार करेंगी।

**32. उप-खंड स्तरीय समिति को याचिका :** (1) ग्राम सभा के संकल्प से प्रीकृत कोई दावेदार संकल्प की तारीख के 60 दिनों के अंदर लिखित या मौखिक रूप से सदस्य सचिव, उप-खंड स्तरीय समिति के सामने साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, जो इसे औपचारिक याचिका के रूप में लेखबद्ध करेगा।

- (2) उप-खंड स्तरीय की समिति याचिका की सुनवाई का दिन नियत करेगी जो एक माह से अधिक बाद का नहीं होगा और वन अधिकार समिति के माध्यम से अपीलकर्ता और संबद्ध ग्राम सभा को सूचना देगी तथा सुनवाई के कम से कम 15 दिन पहले ऐसे ग्राम में एक सुविधा जनक स्थल पर इसकी सूचना लगाएगी।

(3) उप-खंड स्तरीय समिति या तो —

(क) याचिका को मंजूर करेगी, या

(ख) याचिका को अस्वीकार करेगी, या

(ग) 60 दिनों के भीतर विचार के लिए संबद्ध ग्राम सभा के पास याचिका को निर्दिष्ट करेगी।

(4) ऐसे निर्देश की प्राप्ति के बाद ग्राम सभा 30 दिनों के भीतर बैठक करेगी, अपीलकर्ता को सुनेगी और उस निर्देश के बारे में एक संकल्प पारित करेगी एवं इसकी सूचना उप-खंड स्तरीय स्तर की समिति को देगी।

(5) उप-खंड स्तरीय समिति ग्राम सभा के संकल्प पर विचार करेगी और इस निर्देश पर ग्राम सभा के संकल्प की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर समुचित आदेश पारित करेगी।

(6) लंबित अपीलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उप-खंड स्तरीय समिति अन्य दावेदारों के वन अधिकारों के अभिलेखों की परीक्षा करेगी और इनको मिलाकर अंतिम विनिश्चय के लिए जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेगी।

(7) दो या अधिक ग्राम सभाओं के बीच विवाद के मामले में किसी ग्राम सभा के आवेदन पर या उप-खंड स्तरीय समिति स्वयं ही विवाद को सुलझाने के विचार से संबद्ध ग्राम सभाओं को संयुक्त बैठक के लिए बुलाएगी और यदि तीस दिनों की अवधि के अंदर कोई आपसी सहमति से समाधान नहीं निकलता है तो उप-खंड स्तरीय समिति संबद्ध ग्राम सभाओं की बात सुनने के बाद विवाद का विनिश्चय करेगी और समुचित आदेश पारित करेगी।

33. जिला स्तरीय समिति को याचिका : (1) उप-खंड स्तरीय समिति के प्रस्ताव से पीड़ित कोई दावेदार प्रस्ताव की तारीख के 60 दिनों के अंदर लिखित या मौखिक रूप से सदस्य सचिव, जिला स्तरीय समिति के सामने साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, जो इसे औपचारिक याचिका के रूप में लेखबद्ध करेगा।

(2) जिला स्तरीय समिति याचिका की सुनवाई का दिन नियत करेगी जो एक माह से अधिक पश्चात का नहीं होगा और सदस्य-सचिव के माध्यम से अपीलकर्ता और संबंधित उप-खंड स्तरीय समिति को सूचना देगी तथा सुनवाई के कम से कम 15 दिन पहले ऐसे गांव में एक सुविधा जनक स्थल पर इसकी सूचना लगाएगी।

(3) जिला स्तरीय समिति या तो —

(क) याचिका को मंजूर करेगी, या

(ख) याचिका को अस्वीकार करेगी, या

- (ग) 60 दिनों के भीतर विचार हेतु संबद्ध उप-खंड स्तरीय समिति को याचिका को निर्दिष्ट करेगी।
- (4) ऐसे निर्देश की प्राप्ति के बाद उप-खंड स्तरीय समिति 30 दिनों के भीतर बैठक करेगी, अपीलकर्ता को सुनेगी और उस निर्देश पर सिफारिश करेगी तथा इसकी सूचना जिला स्तरीय समिति को देगी।
- (5) जिला स्तरीय समिति उप-खंड स्तरीय समिति की सिफारिश पर विचार करेगी और ऐसी सिफारिश की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर समुचित आदेश पारित करेगी।
- (6) लंबित अपीलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिला स्तरीय समिति अन्य दावेदारों के वन अधिकारों के अभिलेखों पर विचार और अनुमोदन करेगी तथा सरकार के अभिलेखों में सुधार के लिए निर्देश जारी करेगी।
- (7) दो या अधिक ग्राम सभाओं के बीच विवाद के मामले में किसी उप-खंड स्तरीय समिति के आवेदन पर या जिला स्तरीय समिति स्वयं ही विवाद को सुलझाने के विचार से संबद्ध उप-खंड स्तरीय समितियों को संयुक्त बैठक में मतभेदों को सुलझाने के लिए बुलाएगी और यदि तीस दिनों की अवधि के अंदर कोई आपसी सहमति समाधान नहीं निकलता है तो जिला स्तर की समिति संबंधित उप-खंड स्तरीय समितियों की बात सुनने के बाद विवाद का विनिश्चय करेगी और समुचित आदेश पारित करेगी तथा यह आदेश सभी पर आबद्ध होगा।
- (8) यदि ग्राम सभाओं के बीच विवाद के मामले में उप-खंड स्तरीय समिति के आदेश से ग्राम सभा पीड़ित है तो उक्त ग्राम सभा द्वारा दिए गए आवेदन पर जिला स्तरीय समिति संबद्ध ग्राम सभाओं के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी और यदि 30 दिनों की अवधि के भीतर आपसी सहमति से समाधान नहीं निकलता है तो जिला स्तरीय समिति संबद्ध ग्राम सभाओं की सुनवाई के बाद विवाद पर विनिश्चय लेगी और एक उपयुक्त आदेश पारित करेगी जो सभी पर आबद्धकारी होगा।

**34. महत्वपूर्ण वन्य जीव आवास की घोषणा और अधिसूचना :** (1) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख के 6 मास के भीतर जनजातीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से संग्रह किए जाने वाले आंकड़ों के स्वरूप, संग्रह करने की प्रक्रिया, आंकड़ों का सत्यापन, इसकी व्याख्या, विशेषज्ञ समिति की भूमिका, अन्य व्यक्तियों से परामर्श की प्रक्रिया के साथ महत्वपूर्ण वन्य जीव आवास का अवधारण करेगा।

- (2) ये मार्गदर्शक सिद्धांत जैव विविधता और वन्य जीव तथा विरासत स्थलों, पारिस्थितिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों, अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों जैसे संभावित जैव विविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माने गए क्षेत्रों के दस्तावेज से संबंधित विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे।

**उपाबंध - I**  
**[नियम 8 (ट) देखें]**  
**प्रारूप - क**

**वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप**  
**[नियम 27 (1) देखें]**

1. दावेदार (री) का/के नाम
2. पति/पत्नी का नाम
3. पिता/माता का नाम
4. पता :
5. ग्राम :
6. ग्राम पंचायत:
7. तहसील/तालुका :
8. जिला:
9. (क) अनुसूचित जनजाति : हां/नहीं  
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

(ख) अन्य परम्परागत वन निवासी : हां/नहीं

(क्या पति/पत्नी अनुसूचित जनजाति से है (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

10. परिवार के अन्य सदस्यों का नाम और आयु:  
(बच्चों व वयस्क आश्रितों सहित)

**भूमि पर दावे का स्वरूप:**

1. अधिभोग की गई भूमि का उपयोग  
क) निवास के लिए  
ख) स्वयं खेती के लिए, यदि कोई हो:  
(अधिनियम की धारा 3 (1) (क) देखें)
2. विवादित भूमि, यदि कोई हो:  
(अधिनियम की धारा 3 (1) (घ) देखें)
3. पट्टे/घुसियों/अनुदान, यदि कोई हो:  
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ङ) देखें)
4. यथावत पुनर्प्राप्त हेतु भूमि या आनुकूलिक भूमि, यदि कोई हो:  
(अधिनियम की धारा 3 (1) (च) देखें)
5. भूमि जहां से बिना मुआवजा दिए, विस्थापित किए गए हैं:  
(अधिनियम की धारा 4 (b) देखें)
6. वन प्रांगों में भूमि का विस्तार, यदि कोई हो:  
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ज) देखें)
7. अन्य कोई पारंपरिक अधिकार, यदि कोई हो:  
(अधिनियम की धारा 3 (1) (झ) देखें)
8. समर्थन में सहायक:  
(नियम 31 देखें)
9. अन्य कोई सूचना :

**दावेदार (री) के**  
**हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान**

## प्रकार - ख

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा  
[नियम 27 (1) देखें]

1. दावेदार (री) का नाम :  
क. एफडीएसटी समुदाय : हां/नहीं  
ख. ओटीएफडी समुदाय : हां/नहीं
2. ग्राम :
3. ग्राम पंचायत :
4. तहसील/तालुका :
5. जिला :

प्रयोग किए गए सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-

1. सामुदायिक अधिकार जैसे निस्कार यदि कोई हो :  
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें)
2. गौन वन उत्पादों पर अधिकार यदि कोई हो :  
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)
3. सामुदायिक अधिकार  
क. उपयोग या पत्रता (मछली, जलसन्ध) यदि कोई हो :  
ख. बस्ने हेतु यदि कोई हो :  
ग. पारंपरिक संरक्षणों तक बंजारों और पशुपालकों की पहुंच यदि कोई हो :  
(अधिनियम की धारा 3 (1) (घ) देखें)
4. पीटीजी व आरंभिक कृषि समुदायों के लिए पर्याप्त और अधिकतम की सामुदायिक अवधियां यदि कोई हो :  
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ङ) देखें)
5. जैव विविधता तक वैज्ञानिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच का अधिकार यदि कोई हो :  
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें)
6. अन्य पारंपरिक अधिकार यदि कोई हो :  
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें)
7. समर्थन का साक्ष्य :  
(नियम 31 देखें)
8. अन्य कोई सूचना :

दावेदार (री) का हस्ताक्षर/  
अंगूठे का निशान

उपाबंध - 2

[नियम 8 (3) (ख) देखें]

अधिमोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

[नियम 18 देखें]

1. वन अधिकारों के धारक (कों) का/के नाम (पति-पत्नी सहित) :
2. पिता/माता का नाम :
3. आश्रितों का नाम :
4. पता :
5. ग्राम/ग्राम समा :
6. ग्राम पंचायत :
7. तहसील/तालुका :
8. जिला :
9. अनुसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी :
10. क्षेत्रफल
11. खसरा/कंपार्टमेंट सं. सहित प्रमुख निशानों द्वारा सीमाओं का विवरण :
12. यह भूमि विरासत में मिल सकती है पर अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहस्ताक्षरी, ..... (राज्य का नाम) सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

मंडलीय वन अधिकारी/उप वन संरक्षक

जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी

जिला कलेक्टर/उप आयुक्त

**सामुदायिक वन अधिकारों के लिए हक**  
[नियम 12 देखें]

1. सामुदायिक वन अधिकार के धारक (कों) का/के नाम :  
(उपाबंध के अनुसार)
2. ग्राम/ग्राम सभा :
3. ग्राम पंचायत :
4. तहसील/तालुका :
5. जिला :
6. अनुसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी :
7. सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप
8. शर्तें यदि कोई हों
9. निम्नलिखित के साथ सीमाओं का विवरण  
रूढ़िजन्य सीमा और/या खसरा/कंपार्टमेंट सं.  
सहित प्रमुख पहचान चिन्ह

हम, अधोहस्ताक्षरी \_\_\_\_\_, (राज्य का नाम) सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

मंडलीय वन अधिकारी/उप वन संरक्षक

ज़िला जनजातीय कल्याण अधिकारी

ज़िला कलेक्टर/उप आयुक्त

**उपाबंध**

सामुदायिक वन अधिकार का/के धारक (कों) का/के नाम

1. ....
2. ....
3. ....

हम, अधोहस्ताक्षरी \_\_\_\_\_, (राज्य का नाम) सरकार के लिए और उसकी ओर से, सामुदायिक वन अधिकारों के उपरोक्त उल्लिखित धारकों के हक में यथा उल्लिखित वन अधिकार की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

मंडलीय वन अधिकारी/उप वन संरक्षक

ज़िला जनजातीय कल्याण अधिकारी

ज़िला कलेक्टर /उप आयुक्त

## MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2007

**G.S.R. 437(E).**— The following draft rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 14 of the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) is hereby published, as required under sub-section (1) of the said section for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette containing this notification is made available to the public.

Any objection or suggestion which may be received from any person in respect of the said draft rules within the period so specified shall be considered by the Central Government.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Tribal Affairs, 7<sup>th</sup> Floor, A-Wing, Shastri Bhawan, New Delhi – 110001.

## DRAFT

**The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers  
(Recognition of Forest Rights) Rules, 2007**

Chapter I

## Preliminary

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.



**2. Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires:-

- (1) "Act" means the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007);
- (2) "bonafide livelihood needs" means fulfillment of sustenance needs of self and family through consumption and /or sale of produce from forest land or forest based uses, and stones and fuel wood for house or household purposes;
- (3) "Claimant" means an individual, group of individuals, family or community applying for recognition and vesting of any of the rights listed in the Act;
- (4) "Forest Rights Committee" means a committee elected by the Gram Sabha under rule 26(2);
- (5) "other traditional right" means any other traditional right customarily enjoyed by the forest dwelling Scheduled Tribes or other traditional forest dwellers whether recorded or not and shall include right to traditional agricultural practices;
- (6) "primarily reside in and depend on the forests or forest lands" in section 2(c) and section 2(o) of the Act - means those claimants who are dependent on such forest or forest land for bonafide livelihood needs but who need not exclusively and necessarily reside on such forest or forest land;
- (7) "Section" means the section of the Act;
- (8) "Sustainable use" shall have the same meaning assigned to it in clause(o) of section 2 of the Biological Diversity Act, 2002, (18 of 2003) that is, the use of components of biological diversity in such manner and at such rate that does not lead to the long-term decline of the biological diversity thereby maintaining its potential to meet the needs and aspirations of present and future generations.

**Chapter II****Gram Sabha and various committees****3. Gram Sabha and its functions.-** (1) The Gram Sabha shall be the authority,-

- (a) to determine the nature and extent of forest rights;
- (b) to communicate with regard to such with the Sub-Divisional Level Committee;
- (c) to receive, hear and settle disputes on such claims under the Act;
- (d) to prepare a list of claimants of forests rights and maintain a register of claims; and
- (e) to pass a resolution on claims on forest rights and forward the same to Sub Divisional Level Committee in terms of the provisions contained in the Act and rules made thereunder.

(2) The quorum of the Gram Sabha meeting shall be not less than two thirds of the adult members of such Gram Sabha where at least thirty three percent shall be

women. Where there is a heterogeneous population of Scheduled Tribes and non Scheduled Tribes in any village, at least two thirds of the Scheduled Tribe members shall be present to constitute the quorum, and members of the primitive tribal groups and pre-agricultural communities shall be adequately represented.

**Explanation:-**

For the purposes of this rule, the following shall constitute the Gram Sabha of the village:-

- (a) in Scheduled Areas under the Provisions of Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 or any other corresponding law in force in the State, the persons whose names are included in the electoral rolls for the Panchayat at the village, which comprises a hamlet or a group of hamlets managing their affairs in accordance with their traditions and customs, and resolve to constitute a Gram Sabha for the purposes of the Act and intimate the same to the concerned Gram Panchayat and the Sub-Divisional Level Committee;
  - (b) in States where there are Panchayats and which are not Scheduled Areas, the Gram Sabha of the Panchayat if authorized to organize Gram Sabha meetings at smaller village units in a large village for the purposes of the Act and intimate the same to the concerned Gram Panchayat and the Sub-Divisional Level Committee;
  - (c) in case of section 2(p)(iii) of the Act, the adult members of such village may resolve to constitute a Gram Sabha and intimate the same to the adjoining Gram Panchayat(s) and Sub Divisional Level Committee;
  - (d) in states where there are no Panchayats, the adult members of traditional village institutions by what ever name called may resolve to constitute Gram Sabha and intimate the same to the Sub Divisional Level Committee.
4. The State Government shall, within a period of three months from the date of notification of these rules, constitute the Sub-Divisional Level Committee, District Level Committee and State Level Monitoring Committee for the purpose of the Act and the rules made thereunder.
5. **Sub-Divisional Level Committee.-** The Sub-Divisional Level Committee shall be constituted with the following members, namely:-
- (a) Sub-Divisional Officer as Chairperson;
  - (b) Forest Officer in charge of a Sub-division;
  - (c) three members of the Block/ Tehsil Panchayats nominated by the District Panchayat of whom two shall be the Scheduled Tribe member preferably

those who are forest dwelling or who belong to the primitive tribal groups and where there are no Scheduled Tribes member, two members who are preferably other traditional forest dwellers and at least one shall be a woman member; or in areas covered under the Sixth Schedule of the Constitution, three members nominated by the Autonomous District Council/ Regional Council or other appropriate zonal level, at least one being a woman member;

(d) an officer of the Tribal Welfare Department in-charge of the Sub-division or where such officer is not available a corresponding officer in charge of tribal affairs as Member-Secretary.

**6. Functions of the Sub-Divisional Level Committee.-** The Sub-Divisional Level Committee shall -

- (a) provide forest and revenue maps and electoral rolls to the Gram Sabha or the Forest Rights Committee;
- (b) collate all the resolutions of the concerned Gram Sabhas;
- (c) consolidate maps and details provided by the Gram Sabhas;
- (d) examine the resolutions and the maps of the Gram Sabhas to ascertain the veracity of the claims;
- (e) hear and adjudicate disputes between Gram Sabhas on the nature and extent of any forest rights;
- (f) hear petitions from persons aggrieved by the resolutions of the Gram Sabhas;
- (g) co-ordinate with other Sub-Divisional Level Committee for inter sub-divisional claims;
- (h) prepare block/ tehsil-wise draft record of forest rights after reconciliation of government records;
- (i) forward the claims with the draft record of forest rights through the Sub-Divisional Officer to the District Level Committee for final decision;
- (j) raise awareness through workshops and other means about the objectives, provisions and procedures of the Acts and in rule 25(4);
- (k) ensure easy and free availability of proforma of claims to the claimants as provided in Annex-I to these rules.

**7. District Level Committee.-** The District Level Committee shall be constituted with the following members, namely:-

- (a) District Collector or Deputy Commissioner as Chairperson;
- (b) concerned Divisional Forest Officer or Deputy Conservator of Forest;
- (c) three members of the district panchayat nominated by the district panchayat, of whom two shall be Scheduled Tribe members preferable those who are forest dwellers or who belong to members of the primitive tribal groups and where there are no Scheduled Tribe members, two

members who are preferably other traditional forest dwellers and at least one shall be a woman member ; or in areas covered under the Sixth Schedule of the Constitution, three members of the Autonomous District Council /Regional Council at least one being a woman member.

- (d) an officer of the Tribal Welfare Department in-charge of the district or where such officer is not available, a corresponding officer in charge of tribal affairs as Member Secretary.

**8. Functions of District Level Committee.-** (1) The District Level Committee shall -

- (a) examine whether all claims have been addressed keeping in mind the objectives of the Act;
- (b) consider and finally approve the claims and record of forest rights prepared by the Sub-Divisional Level Committee;
- (c) hear petitions from persons aggrieved by the orders of the Sub-Divisional Level Committee;
- (d) co-ordinate with other districts regarding inter-district claims;
- (e) issue directions for incorporation of the forest rights in the relevant government records including record of rights.

(2) The District Level Committee shall also -

- (a) facilitate the Gram Sabha in accessing government documents, and other relevant information in determining forest rights and provide technical assistance if required;
- (b) ensure dissemination processes and awareness programmes on the Act and rules made thereunder.
- (c) ensure that the Gram Sabhas are conducted in a free, open and representative manner with full and unrestricted participation of women.

(3) The District Collector or Deputy Commissioner shall be responsible for -

- (a) publishing the record of forest rights as finalized by the District Level Committee;
- (b) ensure that a certified copy of the record of forest rights and title under the Act, as specified in Annex-II to these rules, is provided to the concerned claimant and the Gram Sabha and publicly posted at convenient places in the village;

**9. State Level Monitoring Committee. -** The State Level Monitoring Committee shall be constituted with the following members, namely:-

- (a) Chief Secretary as Chairperson;
- (b) Secretary, Revenue Department;
- (c) Secretary, Tribal Welfare Department;
- (d) Secretary, Forest Department;

- (e) Principal Chief Conservator of Forests;
  - (f) Commissioner, Tribal Welfare or equivalent as Member-Secretary;
  - (g) three Scheduled Tribes member of the Tribes Advisory Council, nominated by the Chairperson of the Tribes Advisory Council and three independent experts on forest & wildlife, tribal and gender issues to be nominated by the State Government and where there is no Tribes Advisory Council, three independent experts of forest & wildlife, tribal and gender issues to be nominated by the State Government.
- 10. Functions of the State Level Monitoring Committee.-** The State Level Monitoring Committee shall -
- (a) monitor the process of recognition, verification and vesting of forest rights in the State;
  - (b) devise criteria and indicators for monitoring the effectiveness of the process of recognition and vesting of forest rights;
  - (c) co-ordinate with other State Government and State Level Monitoring Committees in case of inter-state claims;
  - (d) furnish a six monthly report on the process of recognition, verification and vesting forest rights and submit to the nodal agency such returns and reports as may be called for by the nodal agency;
  - (e) on receipt of any such notice as mentioned in section 8 of the Act, the State Level Monitoring Committee may take appropriate actions against such authorities under the Act where such offence is established and take corrective measures;
  - (f) monitor the resettlement as provided under the Act.

### Chapter III

#### **Forest Rights of Forest Dwelling Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers**

**11. Rights to occupation:-** (1) In case of rights claimed under clause (a) of sub-section (1) of Section 3 of the Act, the family may consist of a nuclear family and their minor children and may include any person wholly or substantially dependent on the family.

(2) In case of land under occupation by the community under sub-section (6) of Section 4 of the Act or under common occupation as under clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Act, the area under actual use may be recognized and vested with the community up to a maximum of four hectares.

**12. Community rights such as Nistar.-** The community rights such as *nistar*, as recognized in different States by whatever name shall be considered for bonafide livelihood needs.

**13. Rights to minor forest produce.-** (1) The rights under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Act shall include all minor forest produce regardless of whether they are nationalized or previously restricted or prohibited and all items provided in State Acts and rules, orders and directions issued thereunder.

(2) The Gram Sabha shall ascertain the nature of minor forest produce which has been traditionally collected within or outside the village boundaries in accordance with the Act and intimate the Sub-Divisional Level Committee.

(3) The access, collection, use and disposal of all such minor forest produce by holders of forest rights shall be free of royalty.

(4) The exercise of these rights shall extend to areas where such minor forest produce has been traditionally collected and includes non contiguous and non exclusive, forest lands and community forest resources.

(5) The exercise of rights to minor forest produce includes local level processing, value addition and marketing by the gatherer or their co-operative or their collective associations.

(6) The exercise of rights includes transport of minor forest produce through head loads or cycles and hand-carts to the nearest village or collection point.

(7) The Gram Sabha shall ensure that the exercise of right under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Act also includes the responsibility of sustainable use and prevention of any destructive practices in collection of such minor forest produce.

**14. Right to other community rights and entitlements.-** (1) The community which has been traditionally using water bodies shall have the right over the fish and other products of such water bodies while ensuring its sustainable use.

(2) No license shall be granted by any Government agency on such water bodies without negotiated agreement and prior informed consent of such community.

(3) The exercise of rights in respect of nomadic and pastoral communities over their community forest resources includes forest lands under traditional, customary and season usage, which may not necessarily constitute a single contiguous area and may be shared with other Scheduled Tribes or other traditional forest dwellers.

(4) The claim from pastoralists and nomadic tribes and other seasonal users for determination of their rights under clause (d) of sub-section (1) of section 3 of the Act may either be through individual members, the community or traditional community institution and shall be verified at a time when such individuals, communities or their representatives or representative of their traditional institutions are present.

**15. Right to community tenure of habitat and habitation.-** (1) The habitat for primitive tribal groups and pre-agricultural communities shall have the same inclusive meaning as community forest resource and in particular, non-contiguity and non-exclusiveness.

(2) The claim from member of a primitive tribe or pre-agricultural community for determination of their rights to habitat under clause (e) of sub-section (1) of section 3 of the Act may either be through their community or traditional community institution and shall be verified at a time when such communities or their representatives or representative of their traditional institutions are present.

(3) The primitive tribal groups and pre-agricultural communities may delineate and determine their customary habitat in consultation with traditional institutions wherever possible, the Gram Sabha and the Sub-Divisional Level Committee.

(4) In case the primitive tribal groups and pre-agricultural communities do not claim their right under clause (e) of sub-section (1) of section 3 of the Act, the Sub-Divisional Level Committee may *suo motu* and subject to prior notice to the concerned Gram Sabha, initiates the process to determine the forest rights of such vulnerable communities.

**16. Rights over disputed lands.-** (1) If any rights over disputed lands are being claimed under clause (f) of sub-section (1) of section 3 of the Act, then it shall include right in lands in 'deemed' Reserved Forests, or forest lands where the process of forest settlement has been incomplete in any manner including incorrect records or non-adherence to due process of laws, or forest lands where final notification under section 20 of the Indian Forest Act, 1927 or corresponding section of any other relevant Act is yet to be issued or lands over which, there are conflicting claims between different Government departments and thereby affecting people's rights.

(2) The presumption of rights over such disputed lands shall be in favour of the claimant unless otherwise decided after giving a reasonable opportunity of being heard in the matter.

**17. Rights for conversion of *pattas*, Leases and Grants.-** (1) The rights for conversion of *pattas*, leases and grants on any description of forest lands being claimed under clause (g) of sub-section (1) of section 3 of the Act to titles, shall include among others, lands which have become contentious between different Government departments, or forests lands whose transfer has not been completed; or *pattas* in Orange Areas of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Ek Sali leases, Dalhi lands in Maharashtra or leases for agro-forestry, agro-silvi or fireline

plots or lands whose leases have not been renewed or who may have been evicted without due process of law; *pattas* in forest villages and *pattas* issued but cancelled or extinguished without following the due process of law.

**18. Right to conversion of forest villages and unrecorded settlements into revenue villages.**— When rights are being claimed for conversion of a forest village into a revenue village under clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Act:

- (a) any settlement on forest land which is not a revenue village or part thereof shall be considered eligible, and
- (b) the land granted to dwellers of revenue villages created out of forest villages or such settlements shall be sustainably used for bonafide livelihood needs and shall not be put to ecologically damaging commercial use in any form.

**Note:** The community rights conferred under rules 11 to 18 above shall not be alienable, transferable, leased or rented out.

**19. Right to protect, regenerate, conserve or manage community forest resources.**— (1) Prior to determination of the rights under clause (i) of sub-section (1) of section 3 of the Act, the Gram Sabha shall initiate the process of determination of the nature and extent of rights over community forest resources where evidence mentioned in sub-rule (3) of rule 31 shall be taken into consideration.

(2) Where two or more communities have rights over the same community forest resource, a joint group of the communities shall be convened by the concerned Gram Sabhas and shall exercise their rights under the supervision and control of the concerned Gram Sabhas.

(3) In order to confirm the customary boundaries of the community forest resource, the Forest Rights Committees of the respective Gram Sabha shall initiate the determination of the community forest resource with the agreement of all concerned Gram Sabha on a mutually acceptable date and intimate to the respective Gram Sabha and Sub-Divisional Level Committee in writing.

(4) The customary boundaries shall not be treated as alteration of existing statutory boundaries.

**20. Rights in Autonomous District Councils and Regional Councils.**— The forest rights which are already recognized under any State law or laws of any Autonomous District Councils or Regional Councils or rights which are available under any traditional or customary law of the concerned tribes of any State, shall be exercised in accordance with the respective laws of the Autonomous District Councils, Regional Councils, such traditional or customary law of the concerned tribes or the State Governments.



**21. Right to intellectual property and biodiversity.-** (1) When a right of access to biodiversity and community right to intellectual property and traditional knowledge related to biodiversity and cultural diversity has been recognised under clause (k) of sub-section (1) of the Act, it shall include rights to regulate access, control, develop and protect traditional science and technology associated with biodiversity resources including genetic resources, seeds, medicines, health practices, medicinal plants, agriculture, knowledge of fauna and flora, minerals and other indigenous knowledge systems and practices.

(2) The Gram Sabha may co-ordinate with the Biodiversity Management Committee under the Biological Diversity Act, 2002 to document the biodiversity resources being conserved, sustainably used and managed by it, as well as the individual, group or community knowledge associated with such biodiversity and cultural diversity and voluntarily disclosed by knowledge providers for recording by the Gram Sabha.

(3) The documentation referred to in sub-rule (2) shall be the property of Gram Sabha and it shall decide on which of its parts or contents are to be made freely available to the public and the terms and conditions under which other parts or contents may be disclosed to the parties.

(4) The Gram Sabha may co-ordinate with the State Biodiversity Boards as well as the Protected Plant Varieties and Farmers' Rights Authority in the management of such documented knowledge to promote assertion of pertinent intellectual property rights and ensure equitable sharing of benefits from its use.

(5) The Gram Sabha may co-ordinate with the Biodiversity Management Committee to regulate access to biodiversity resources by outsiders and to levy collection charges and work out benefit sharing arrangements.

**22. Right to *in situ* rehabilitation.-** (1) When a right to *in situ* rehabilitation is claimed under clause (m) of sub-section (1) of section 3 of the Act, the burden of proving legal eviction or displacement or receipt of legal entitlement to rehabilitation shall rest with the State or agency acting under the aegis of the State.

(2) The claims may be filed either before the Gram Sabha having jurisdiction with regard to original residence or the Gram Sabha where the claimant has the current residence.

**23. Right to land for displaced.-** (1) When a right to land is claimed under sub-section (8) of section 4 of the Act, the factum of displacement without land

compensation as established by the claimant, shall be the primary basis for the right.

(2) The burden of establishing the use of such land within five years, for the purposes for which it was acquired, rests with the State or agency acting under the aegis of the State.

(3) The claims may be filed either before the Gram Sabha having jurisdiction with regard to original residence or the Gram Sabha where the claimant has the current residence.

#### Chapter-IV

#### Duties of holders of forest rights

**24. Duties of holders of forest rights, gram sabhas and village level institutions.-(1)** The village-level institution or the Gram Sabha may perform the duties falling under section 5 of the Act on behalf of holders of any forest right and shall be empowered to:

- (a) prepare a plan for the protection and management of community forest resources and such plans, norms, methods, procedures, may harmonize its prescriptions with those of relevant plans, such as, forest working plans, management plans of sanctuaries and national parks, biodiversity management plans, watershed management plans and eco-development plans;
  - (b) prepare and adopt norms including institutional arrangements for the protection of, and regulation of access to and sustainable use of the community forest resource; and resources within it including biodiversity, forest, catchments areas, water sources and ecologically sensitive areas,
  - (c) prepare norms for community wildlife management;
  - (d) evolve procedures to protect, conserve, regenerate or manage the resource while protecting interests in forest rights of vulnerable groups and women, including deciding on allowing or denying access to outsiders and charging fees; and
  - (e) evolve methods for monitoring and implementing such norms.
- (2) The Gram Sabha may -
- (a) request the assistance of the Forest Department or other local authorities for implementing its norms, and such authorities shall provide the requisite assistance;
  - (b) take corrective actions as may be necessary, where there is violation of norms created by it in exercise of this right or direct the concerned authorities to proceed in accordance with law;
  - (c) guide the functioning of Joint Forest Management Committee, Eco-

development Committee, Watershed Committee, Biodiversity Management Committee or any other such committees or institutions concerned with the management of forest resources.

(3) In case there is a conflict between a decision of a Gram Sabha and a user group in regard to exercise of rights under clause (i) of sub-section (1) of section 3 of the Act, the decision of the Gram Sabha shall prevail while ensuring that forest rights of vulnerable groups and women are not put to any disadvantage.

### Chapter-V

#### **Responsibility of authorities and procedure for vesting of forest rights**

**25. Processes to sensitize authorities and others.-** (1) The nodal agency shall -

- (a) ensure that awareness is created about the objectives, provisions and procedures of the Act and the rules through various measures including awareness programmes and printed material such as posters in the regional language;
- (b) ensure the translation and publication of the Act and the rules in all the regional languages and arrange to distribute to all Gram Sabhas, Forest Rights Committees and all departments of the Government including Panchayati Raj, Rural Development, Tribal and Social Welfare and Forest Departments;
- (c) undertake the orientation of officials, civilian representatives and non-Government organisations in every State, who can then be called upon to assist as resource persons in the awareness programmes;
- (d) sensitise the District Level Committees on the objectives, provisions and procedures of the Act and the rules through the State Governments.

(2) The District Level Committee shall undertake awareness campaigns on the objectives, provisions and procedures of the Act and the rules through traditional and other means and ensure that the Act and the rules are printed in regional languages and distributed in the offices and prominent places at the village, block and sub-divisional level and special efforts are taken in particular to ensure that the information reaches the settlements located in remote areas.

(3) The District Level Committee shall raise awareness through workshops and other means to sensitize members of the Sub-Divisional Level Committee, officials of Panchayati Raj, Rural Development, Agriculture, Education, Forest, Tribal and Social Welfare departments, on the objectives, provisions and procedures of the Act the rules.

(4) The Sub-Divisional Level Committee shall organize for each tehsil or block in the sub-division, one or more awareness camps to sensitize members of the Gram

Sabhas including Forest Rights Committees, civilian representatives including teachers, women's groups, political leaders, social workers activists and lawyers to acquaint them with the objectives, provisions and procedures of the Act and the rules.

**26. Procedure for filing and determination of claims by Gram Sabha.-** (1) The Sub-Divisional Level Committee shall, within three months from the date of the coming into force of these rules, notify the dates of the first meeting of the Gram Sabha.

(2) In its first meeting, the Gram Sabha shall elect from amongst its members a committee of at least seven persons where three members shall be Scheduled Tribes, three members shall be women and one shall be other traditional forest dweller; and where there are no Scheduled Tribes, at least three members shall be other traditional forest dweller and three shall be women and such committee shall be known as the Forest Rights Committee and the same shall be intimated to the concerned Sub-Divisional Level Committee.

(3) The Gram Sabha may elect not more than seven members, in addition to the members mentioned in sub-rule (2), in the Forest Rights Committee if they so desire while keeping the same proportion of Scheduled Tribes, other traditional forest dwellers and women as specified in sub-rule (2).

(4) The Gram Sabha shall be provided with necessary infrastructure and financial support from the Government.

(5) The Forest Rights Committee shall assist the Gram Sabha in its functions to -

- (i) conduct the Gram Sabha meeting;
- (ii) receive, acknowledge and retain the claims in the specified form and evidence in support of such claims;
- (iii) call for necessary assistance from government functionaries such as school teachers, village level workers, foresters and patwaris;
- (iv) verify claims as provided in these rules;
- (v) call for evidence or support from any authorities or agency or persons as required;
- (vi) prepare the record of claims and evidence including maps;
- (vii) prepare a list of claimants on forest rights;
- (viii) present their findings on the nature and extent of the claim before the Gram Sabha for its decision.

**27. Verification of claims.-** (1) The Gram Sabha in its first meeting shall -

- (a) call for claims and authorize the Forest Rights Committee to accept such claims in the specified form as provided in Annex-I of these rules and such claims shall be made within a period of three months;

Provided that the Gram Sabha may extend such time limit after recording the reasons thereof.

(b) fix a date for determination of its community forest resource and intimate the same to the adjoining Gram Sabhas where there are potential overlaps and the Sub-Divisional Level Committee.

(2) Any claim which is not in accordance with the specified proforma shall be returned for rectification and then it will be accepted.

(3) All claims under these rules shall at least be accompanied with more than one evidence mentioned in rule 31.

(4) The Gram Sabha may grant time to the claimant to produce evidence before determination of his claim.

(5) The claimant may seek the assistance of Forest Rights Committee in obtaining the relevant evidence.

(6) Every claim received shall be duly acknowledged in writing by the Forest Rights Committee.

**28. Process of verifying claims by Forest Rights Committee.-** (1) The Forest Rights Committee shall, after due intimation to the concerned claimant -

(a) visit the site and physically verify the nature, extent of the claim and evidence on the site; and

(b) receive any further evidence or record, or any oral evidence adduced by the claimant and witnesses.

(2) The Forest Rights Committee may call for evidence from any authority as may be necessary.

(3) The Forest Rights Committee shall then record its findings on the claim and present the same to the Gram Sabha for its decision.

(4) If there are conflicting claims within the traditional or customary boundaries of another village or if the forest area is used by more than one Gram Sabha, the Forest Rights Committees of the respective Gram Sabha shall meet jointly to agree to the nature of enjoyment of such claims and submit the said agreement to the respective Gram Sabhas in writing:

Provided that if they do not come to an agreement, on the competing claims, it shall be resolved by the Sub-Divisional Level Committee.

(5) On a written request of the Gram Sabha or the Forest Rights Committee requesting for information, records or documents, the various departments of the State Government (at all levels), shall provide the same to the Forest Rights Committee or Gram Sabha and explain the same when required and necessary, through an officer authorised for this purpose.

(6) The Forest Rights Committee shall prepare and authenticate a map with the concerned revenue and forest authorities delineating the area of each recommended claim indicating recognizable landmarks.

**29. Determination of the forest rights.**— (1) The Gram Sabha, subsequent to the first meeting as per sub-rule (2) of rule 26, shall meet, as and when required, to consider the findings and recommendations of the Forest Rights Committee and pass appropriate resolutions as deemed fit, but not less than once every two months with prior notice.

(2) The Gram Sabha may then forward a copy of the resolution to the Sub-Divisional Level Committee for necessary action.

(3) If any Gram Sabha fails to perform its functions under section 6 the Act, the Sub-Divisional Level Committee, on an application of a claimant, shall give a notice to the said Gram Sabha for performing such functions, and if the said Gram Sabha does not initiate the process within two months then any claimant may directly approach the Sub-Divisional Level Committee for determination of their claim.

**30. Special provisions for North-Eastern States.**— In the case of the North Eastern States, the claimant shall be, otherwise, under the Acts, rules and regulations in force eligible to hold land and live in the area in question.

**31. Evidence for determination of forest rights.**— (1) The documentary and oral evidence for recognition and vesting of forest rights under section 3 of the Act includes but is not limited to the following, namely:—

- (a) public documents, Government records such as Gazetteers, Census, survey and settlement reports, maps, satellite imagery, working plans, management plans, micro-plans, forest enquiry reports, other forest records, record of rights by whatever name called, *pattas* or leases (conditional or otherwise, expired or otherwise), reports of committees and commissions, Government orders, notifications, circulars, resolutions and letters;
- (b) Government authorised documents such as voter identity card, ration card, passport, loans, insurance and credits and house tax receipts, domicile certificates;

- (c) statements of elders, members of the Gram Sabha and other eligible right holders reduced to writing especially those who cannot read or write, before such Gram Sabha;
- (d) physical attributes such as permanent improvements made to land including leveling, bunds, check dams and the like;
- (e) quasi-judicial and judicial records including court orders, judgments, preliminary offence report by whatever name called, challan and receipts ;
- (f) local inquiry report of spot verification of claims by Forest Rights Committee so elected by the Gram Sabha and approved by the Gram Sabha;
- (g) prior research or documentation of reputed institutions or individuals, including reports, publications of anthropologists and reports of the Anthropological Survey of India;
- (h) any record including maps, record of rights, privileges, concessions, favours, from erstwhile princely State or province or other such intermediaries;
- (i) prior applications, memoranda, petitions made to authorities including courts;
- (j) prior resolutions of the Gram Sabha;
- (k) written accounts of customs and traditions which illustrate the enjoyment of any forest rights and having a force of customary law;
- (l) traditional structures or pictures establishing antiquity or showing long term occupation such as those of old improvements, wells, burial grounds, sacred places;
- (m) historical accounts, survey plans and sketch maps, pictures and descriptive histories of traditional communal forests and hunting grounds, traditional landmarks;
- (n) oral or written genealogy tracing ancestry to individuals mentioned in earlier land records or recognized as having been legitimate resident of the village at an earlier period of time.

(2) The Gram Sabha, the Sub-Divisional Level Committee and the District Level Committee shall consider, preferably more than one of the above-mentioned evidence in determining the forest rights:

Provided that if there is a dispute between the claimant and any State agency the presumption shall be made in favour of the claimant unless proved otherwise.

(3) An evidence for Community Forest Resources may include –

- (a) community rights such as *nistar* by whatever name called;
- (b) traditional grazing grounds; areas for collection of fuel wood, leaf manure, roots and tubers, fodder, wild edible fruits and other minor forest produce; fishing grounds; irrigation systems; sources of water for

- human or livestock use, medicinal plant collection territories of herbal practitioners;
- (c) remnants of soil and water conservation structures, sacred trees, sacred groves, sacred ponds or riverine areas, burial or cremation grounds;
  - (d) Government records of earlier classification of current Reserve Forest as Protected Forest or as gochar or other village common lands, Memorandum of Understanding with the Forest Department relating to Joint Forest Management; auction of minor forest produce collection rights, earlier or current issue of grazing permits;
  - (e) areas assigned to Large Areas Multipurpose Societies or Forest Labour Cooperatives by whatever name called; areas assigned to Tree Growers' Cooperatives;
  - (f) earlier or current practice of traditional agriculture.

(4) An evidence for determining other traditional forest dwellers also includes but is not limited to -

- (a) physical attributes/ traditional structures or pictures establishing antiquity or showing long-term occupation including wells, burial grounds, sacred places, tombstone;
- (b) written genealogy tracing ancestry to individuals mentioned in earlier land records or recognized as having been legitimate resident of the village at an earlier period of time;
- (c) the Gram Sabha, the Sub-Divisional Level Committee and the District Level Committee shall consider more than one evidence mentioned in this rule in deciding three generations not being less than seventy five years for determining the forest rights.

**32. Petitions to Sub-Divisional Level Committee.-** (1) Any claimant aggrieved by the resolution of the Gram Sabha may within sixty days from the date of the resolution make a petition in writing or may make an oral submission before the Member-Secretary, Sub-Divisional Level Committee who will reduce the same to a formal petition.

(2) The Sub-Divisional Level Committee shall fix the hearing of the petition on a day no later than one month and intimate the appellant and the concerned Gram Sabha through the Forest Rights Committee as well as put notice at a convenient public place in such a village at least fifteen days prior to the hearing.

(3) The Sub-Divisional Level Committee may either -

- (a) allow the petition, or
- (b) reject the petition or
- (c) refer the petition to concerned Gram Sabha for reconsideration within sixty days.



(4) After receipt of such reference, the Gram Sabha shall meet within thirty days, hear the appellant, and pass a resolution on that reference and intimate the Sub-Divisional Level Committee.

(5) The Sub-Divisional Level Committee shall consider the resolution of the Gram Sabha and pass appropriate orders within thirty days of the receipt of the resolution of the Gram Sabha on that reference.

(6) Without prejudice to pending appeals, Sub-Divisional Level Committee shall examine and collate the records of forest rights of the other claimants and submit the same to the District Level Committee for final decision.

(7) In case of a dispute between two or more Gram Sabhas, on an application of any of the Gram Sabhas or the Sub-Divisional Level Committee on its own, shall call for a joint meeting of the concerned Gram Sabhas with a view to resolving the dispute and if no mutual agreed solution can be reached within a period of thirty days, the Sub-Divisional Level Committee shall decide the dispute after hearing the concerned Gram Sabhas and pass appropriate orders.

**33. Petitions to District Level Committee.-** (1) Any claimant aggrieved by the resolution of the Sub-Divisional Level Committee may within sixty days from the date of the resolution file a petition in writing or may make an oral submission before the Member-Secretary, District Level Committee who shall reduce the same to a formal petition.

(2) The District Level Committee shall fix the hearing of the petition on a day no later than one month and intimate the appellant and the concerned Sub-Divisional Level Committee through the Member-Secretary as well as put notice at a convenient public place in such a village of the appellant at least fifteen days prior to the hearing.

(3) The District Level Committee may either -

(a) allow the petition, or

(b) reject the petition or

(c) refer the petition to the concerned Sub-Divisional Level Committee for reconsideration within sixty days.

(4) After receipt of such reference, the Sub-Divisional Level Committee shall meet within thirty days, hear the appellant, and make a recommendation on that reference and intimate the District Level Committee.

(5) The District Level Committee shall consider the recommendation of the Sub-Divisional Level Committee and pass appropriate orders within thirty days of the receipt of such recommendations.

(6) Without prejudice to pending appeals, District Level Committee shall consider and approve the records of forest rights of the other claimants and issue directions for correction of records in the Government.

(7) In case there is a discrepancy between orders of two or more Sub-Divisional Level Committees, the District Level Committee on its own, shall call for a joint meeting of the concerned Sub-Divisional Level Committees with a view to reconcile the differences and if no mutual agreed solution can be reached within a period of thirty days, the District Level Committee shall adjudicate the dispute after hearing the concerned Sub-Divisional Level Committees and pass appropriate orders which shall be binding.

(8) In case of disputes between Gram Sabhas, if any Gram Sabha is aggrieved by an order of the Sub-Divisional Level Committee then, on an application by the said Gram Sabha, the District Level Committee shall call for a joint meeting of the concerned Gram Sabhas with a view to reconcile the differences and if no mutual agreed solution can be reached within a period of thirty days, the District Level Committee shall adjudicate the dispute after hearing the concerned Gram Sabhas and pass appropriate orders which shall be binding.

**34. Declaration and notification of critical wildlife habitat.-** (1) The Central Government in the Ministry of Environment and Forests, may, within six months from the date of coming into force of the rules, and in consultation with the Ministry of Tribal Affairs, issue detailed guidelines regarding the nature of data to be collected, the process for collection, validation of the data, its interpretation, role of Expert Committee, the process of consultations among others in determining the critical wildlife habitat.

(2) These guidelines shall take into account the existing guidelines relating to documentation of biodiversity and wildlife and delineation of areas significant from the perspective of biodiversity such as heritage sites, ecologically sensitive areas, sanctuaries and national parks.

[F. No. 17014/02/2007-PC & V (Vol. IV)]

Dr. BACHITTAR SINGH, Jt. Secy.

**ANNEX - I**  
**[See rule 6(k)]**

**FORM - A**  
**CLAIM FORM FOR RIGHTS TO FOREST LAND**  
**[See rule 27(1)]**

1. Name of the claimant (s):
2. Name of the spouse
3. Name of father/ mother
4. Address:
5. Village:
6. Gram Panchayat:
7. Tehsil/ Taluka:
8. District:
9. (a) Scheduled Tribe : Yes/ No  
(Attach Certificate)  
(b) Other Traditional Forest Dweller: Yes/ No  
If a spouse is a Scheduled Tribe (attach certificate)
10. Name of other members in the family with age:  
(including children and adult dependents)

**Nature of claim on land:**

1. Extent of forest land occupied
  - a) for habitation
  - b) for self-cultivation, if any:  
(See Section 3(1)(a) of the Act)
2. disputed lands if any:  
(See Section 3(1)(f) of the Act)
3. Pattas/ leases/ grants, if any:  
(See Section 3(1)(g) of the Act)
4. Land for *in situ* rehabilitation or alternative land, if any:  
(See Section 3(1)(m) of the Act)
5. Land from where displaced without land compensation:  
(See Section 4(8) of the Act)
6. Extent of land in forest villages, if any:  
(See Section 3(1)(h) of the Act)
7. Any other traditional right, if any:  
(See Section 3(1)(l) of the Act)
8. Evidence in support:  
(See Rule 31)
9. Any other information:

Signature/ Thumb Impression  
of the Claimant(s):

**FORM - B****CLAIM FORM FOR COMMUNITY RIGHTS****[See rule 27(1)]**

1. Name of the claimant(s):
  - a. FDST community: Yes/ No
  - b. OTFD community: Yes/ No

2. Village:
3. Gram Panchayat:
4. Tehsil/ Taluka:
5. District:

**Nature of community rights enjoyed:**

1. Community rights such as *nistar*, if any:  
(See Section 3(1)(b) of the Act)
2. Rights over minor forest produce, if any:  
(See Section 3(1)(c) of the Act)
3. Community rights
  - a. uses or entitlements (fish, water bodies), if any:
  - b. Grazing, if any
  - c. Traditional resource access for nomadic and pastoralist, if any:  
(See Section 3(1)(g) of the Act)
4. Community tenures of habitat and habitation  
for PTGs and pre-agricultural communities, if any:  
(See Section 3(1)(e) of the Act)
5. Right to access biodiversity, intellectual  
property and traditional knowledge, if any:  
(See Section 3 (1)(k) of the Act)
6. Other traditional right, if any:  
(See Section 3(1)(l) of the Act)
7. Evidence in support:  
(See Rule 31)
8. Any other information:

**Signature/ Thumb Impression  
of the Claimant (s):**

**ANNEX - II****[See rule 8(3)(b)]****TITLE FOR FOREST LAND UNDER OCCUPATION****[See rule 18]**

1. Name(s) of holder (s) of forest rights (including spouse):
2. Name of the father/ mother:
3. Name of dependents:
4. Address:
5. Village/gram sabha:
6. Gram Panchayat:
7. Tehsil/ Taluka:
8. District:
9. Scheduled Tribe/ Other Traditional Forest Dweller
10. Area:
11. Description of boundaries by prominent
12. landmarks including khasra/compartment No:
13. This title is heritable, but not alienable or transferable.

We, the undersigned, hereby, for and on behalf of the Government of (Name of the State).....affix our signatures to confirm the above forest right.

**Divisional Forest Officer/ Deputy  
Conservator of Forests**

**District Tribal Welfare Officer**

**District Collector/ Deputy Commissioner**

**TITLE TO COMMUNITY FOREST RIGHTS****[See rule 12]**

1. Name(s) of the holder (s) of community forest right:  
[As per Annex]
2. Village/ Gram sabha:
3. Gram panchayat:
4. Tehsil/ Taluka:
5. District:
6. Scheduled Tribe/ Other Traditional Forest Dweller:
7. Nature of community rights:
8. Conditions if any:
9. Description of boundaries including
10. customary boundary and/or by prominent
11. landmarks including khasra/compartment No:

We, the undersigned, hereby, for and on behalf of the Government of \_\_\_\_\_  
(Name of the State) affix our signatures to confirm the above forest right.

**Divisional Forest Officer/ Deputy  
Conservator of Forests**

**District Tribal Welfare Officer**

**District Collector/ Deputy Commissioner**

**Annex**

**Name(s) of the holder (s) of community forest right:**

1.

2.

3 .....

We, the undersigned, hereby, for and on behalf of the Government of (Name of the State).....affix our signatures to confirm the forest right as mentioned in the Title to the abovementioned holders of community forest rights.

**Divisional Forest Officer/ Deputy  
Conservator of Forests**

**District Tribal Welfare Officer**

**District Collector/ Deputy Commissioner**